

बैंकरप्सी कानून हुआ और सख्त

संदर्भ

सरकार ने दवालिया कानून (Insolvency and Bankruptcy Code अर्थात् IBC) में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करने का नरिणय लया है। सरकार का उद्देश्य संशोधन के माध्यम से इस कानून को और सख्त बनाना है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले लोग तथा संदगिध प्रवर्तक (disqualified promoters) अब दवालिया हो रही कंपनी के लयि बोली प्रक्रया (bidding) में भाग नहीं ले पाएंगे।

- जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाला या इरादतन चूककरत्ता वह व्यक्ती होता है, जो सक्षम होने के बावजूद भी ऋण नहीं चुकाता और ऋण से प्राप्त राशिका अनयत्तर कहीं उपयोग कर लेता है।
- संदगिध प्रवर्तक वे होते हैं जो धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल होते हैं।
- वर्तमान में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) करज़ दाता संस्थाओं की याचिका पर कसिी कंपनी को दवालिया घोषति करने की प्रक्रया शुरू कयि जाने पर नरिणय लेती है। इस दौरान कंपनी के नदिशक बोर्ड (Board of Directors) को भंग कर एक इनसॉलवेंसी पेशेवर को नयुक्त कयि जाता है।
- ये पेशेवर कंपनी के प्रबंधन और ऋणदाता संस्था के साथ मलिकर कंपनी की वत्ततीय स्थति सुधारने और करज़ चुकाने के उपाय ढूंढने की कोशशि करता है। इसके लयि प्रारंभ में छः माह का समय दयिा जाता है, जसिे आगे तीन माह के लयि और बढ़ाया जा सकता है।
- इसके बावजूद भी यदा कंपनी की वत्ततीय स्थति में सुधार नहीं होता और ऋण चुकाने का कोई वकिलप दिखाई नहीं देता तो ऋणदाता संस्था उसकी संपत्तिकाे वकिरय की प्रक्रया शुरू कर सकती है।
- इस दौरान ही गडबड़ी की आशंका रहती है। यह कोशशि की जाती है कऋणदाता संस्था कुछ छूट के बाद बकाया ऋण की रकम स्वीकार कर ले। तकनीकी भाषा में इस कृत्य को 'हेयरकट' कहते हैं।
- इसी कमी का लाभ इरादतन करज़ नहीं चुकाने वाले उठाते हैं। एक तरफ वे कम रकम देकर बैंक का करज़ नपिटाने की कोशशि करते हैं, दूसरी तरफ संपत्तिकाे वकिरय की बोली प्रक्रया में भी भाग लेकर उस पर अपना स्वामत्तिव बरकरार रखने की कोशशि करते हैं।

दवालिया कानून में प्रस्तावति संशोधन इसी प्रवृत्तिकाे रोकने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

- सरकार द्वारा इस कानून में बदलाव अध्यादेश के माध्यम से लाए जाने का प्रमुख कारण ये है कऋणदाता संस्थाओं को अगले माह 12 मामलों पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में सुनवाई है।
- अध्यादेश लागू होने से दवालिया कंपनयिों के प्रवर्तकों की मुश्कलिें बढ़ेंगी और वो दोबारा कंपनयिों में हसिसेदारी नहीं खरीद पाएंगे।
- दवालिया कानून में होने वाले संशोधन से जहाँ सरकारी बैंकों को बड़ा फायदा होगा, वहीं बैंकरप्सी प्रक्रया से गुजर रही भूषण स्टील, मोनेट इस्पात जैसी कंपनयिों के लयि यह एक बुरी खबर है।
- साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आईबीसी के तहत दायर मामलों की बढ़ती संख्या से भी सरकार चत्तित है। अभी तक 300 मामले दायर हो चुके हैं, जनिहें सुलझाने के लयि आवश्यक बुनयािदी ढाँचा NCLT के पास नहीं है।
- कई बैंकों ने आशंका जताई थी कऋणदाता संस्थाओं को दवालिया कानून में बोली प्रक्रया में भाग लेने वालों की स्पष्ट परभाषा नहीं होने का इरादतन करज़ नहीं चुकाने वाले फायदा उठा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव के ज़रयि स्पष्ट परभाषा दी जाएगी। यहाँ ये भी ध्यान रखा गया है कऋणदाता संस्थाओं को दवालिया कानून में भाग लेने वाले प्रवर्तक पर पाबंदी न लगे।